POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2021-23 (RNI.REG.NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2021/अंक 05

मासिक प्रेषण दि. 8 मई, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

प्रकाशन की तिथि : 01 मई, 2021 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! राजस्थान का युवा वर्ग हो या वृद्ध जन मेहनत करने व अपना पसीना बहाने में कभी पीछे रहने वाले नहीं हैं। अब तो प्रदेश की आधी आबादी अर्थात महिला वर्ग भी कदम से कदम मिला कर आगे बढ़ने को आतुर है। पिछले साल कोरोना काल में यह सच्चाई उभरकर सामने आई है। यह साबित हो चुका है कि इस वर्ग की आबादी को जरा सा सहारा मिल जाए तो पूरा प्रदेश आत्मनिर्भर बन जाएगा।

केंद्र सरकार की आर्थिक समीक्षा 2020-21 की तस्वीर साफ करती है कि कोरोना काल में कृषि व सेवा क्षेत्र ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संभाला। यह खुशी की बात है। बाड़मेर और डूंगरपुर ऐसे जिले हैं जहां सर्वाधिक संख्या में 80 साल से अधिक उम्र के वृद्धजन कृषि क्षेत्र और मनरेगा में कठोर श्रम करते सामने आए हैं।

प्रदेश में हुनरमंद और प्रतिभावान युवाओं की कोई कमी नहीं है। सीकर, झुंझुनूं, श्रीगंगानगर एवं भीलवाड़ा के युवाओं ने पिछले दो साल में लघु उद्योग लगाने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। प्रदेश के 5337 युवाओं ने मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत करीब 92127 लाख रुपए का ऋण लेकर कम्प्यूटर सेंटर, फूड प्रोसेसिंग प्लांट, पशु आहार, होटल, प्लास्टिक आइटम व ट्रांसपोर्ट जैसे कई कारोबार में निवेश कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए हैं। इससे उनमें आत्म विश्वास जाग्रत हुआ है।

प्रदेश की नारी शक्ति पुरस्कार विजेता रूमादेवी और आदिवासी टीपू गरसिया जैसी अनेक दस्तकार महिलाओं ने न केवल अपने दम पर विदेशों तक अपनी पहुंच बनाई है, बल्कि गांवों की हजारों महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया है।

महिला सशक्तिकरण के लिए नई महिला नीति के प्रारूप को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में केबिनेट की बैठक में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रदेश की नई महिला नीति के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। मंत्रीमंडल की ओर से

महिलाओं तथा बालिकाओं के समग्र विकास के लिए शीघ्र तैयार होने वाली नई महिला नीति 2021 से महिला एवं बालिका कल्याण के लिए विभिन्न विभागों में बेहतर समन्वय किया जा सकेगा। नई महिला नीति के प्रारूप में खासतौर पर यह शामिल होगा:-

- यह नीति प्रदेश में बालिकाओं, किशोरियों और महिलाओं को सुरक्षित एवं सशक्त बनाने में सहायक होगी ।
- महिलाओं के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे-जन्म, उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण, आजीविका, आवास, संपत्ति के स्वामित्व, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारिता आदि को इसमें शामिल किया गया है।
- यह नीति सतत विकास लक्ष्य 2030 के अनुरूप बनाई गई है। इसमें महिलाओं के विभिन्न समूहों के व्यापक वर्गीकरण पर विशेष फोकस किया गया है।
- इससे इन समूहों के लिए पृथक से लक्ष्य निर्धारित कर उनके कल्याण और समग्र विकास के लिए योजनाएं बनाई जा सकेंगी।

मोतियाबिंद के आपरेशन में लापरवाही

अस्पताल को देना होगा ब्याज सहित हर्जाना

राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग में चुरू निवासी भंवर सिंह ने डॉ. रणजीत सिंह बेनीवाल एवं संबंधित अस्पताल के खिलाफ अपील दर्ज कराई। मामले के अनुसार परिवादी भंवर सिंह रेलवे में कांटेवाला के पद पर कार्यरत है। रेलवे अस्पताल की सलाह पर उन्होंने डॉ. रणजीत सिंह को अपनी आंखे दिखाई। डॉक्टर ने जांच के बाद नेत्रदृष्टि कमजोर बताते हुए छह माह बाद ऑपरेशन करवाने की सलाह दी, लेकिन रेलवे ने उन्हें फिटनेस जारी नहीं किया और उन्होंने दुबारा चैकअप करवाया। इस पर डॉक्टर ने 18 हजार रुपए लेकर ऑपरेशन करके विदेशी लेंस लगाने की बात कही। ऑपरेशन में बरती गई लापरवाही के कारण उनकी आंख की पुतली खराब हो गई। जयपुर और दिल्ली एम्स तक दिखाने के बाद भी उनकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। इसके चलते उनकी नौकरी में ग्रेड भी कम कर दी गई। भंवर सिंह ने इसे राज्य आयोग में चुनौती देते हुए जिम्मेदार अस्पताल व डॉक्टर्स से क्षतिपूर्ति राशि दिलाने की मांग की।

उपभोक्ता आयोग ने मामले की सुनवाई पर अस्पताल व डॉक्टर्स द्वारा बरती गई लापरवाही को सेवादोष, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना और इसके लिए दोषी अस्पताल व डॉक्टर्स पर बीस लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। साथ ही हर्जाना राशि पर 27 जनवरी 2016 से नौ प्रतिशत ब्याज भी अदा करने के आदेश दिए हैं।

गरीब सवर्णों को मिलेगा फायदा

प्रदेश के गरीब सवर्णों के लिए अच्छी खबर है। अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान सरकारी नौकरी की अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलेगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यह छूट 5 साल और महिला अभ्यर्थियों के लिए 10 साल होगी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए है, उन्हें इसका फायदा मिलेगा। अब तक ईडब्ल्यूएस वर्ग को सरकारी सेवा में आरक्षण तो था लेकिन अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं थी। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे ऐसे लोगों के लिए यह एक बड़ा फैसला है।

कोरोना में पढ़ाई भूले नौनिहाल

कोरोनाकाल ने देश के नौनिहालों की शैक्षणिक समझ-बूझ पर जबरदस्त प्रहार किया है। दस महीने तक स्कूल बंद रहने से बच्चे पिछली पढ़ाई भूल गए। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन कक्षाओं का दावा किया गया, मगर स्थिति यह है कि न केवल सरकारी बल्कि निजी स्कूलों के बच्चे भी पढ़ाई में बुरी तरह पिछड़ गए। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति और भी विकट है।

सबसे ज्यादा असर प्राईमरी कक्षाओं के बच्चों पर पड़ा है। प्राईमरी के 92 फीसदी बच्चे पिछली कक्षाओं में पढ़ी गई हिन्दी या अन्य भाषाई योग्यता तक नहीं पहुंचे। वहीं 82 फीसदी बच्चे पिछली कक्षाओं में पढ़ी गणितीय योग्यता को भूल गए। यह चौंकाने वाले आंकड़े राजस्थान सहित पांच राज्यों में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से किए गए सर्वेक्षण में सामने आए हैं।

हक डकार रही बिजली कंपनियां

विद्युत आपूर्ति में व्यवधान, टूटी केबल को सुधारना, खराब मीटर बदलने और अन्य परेशानी निर्धारित समय पर दूर नहीं होने पर उपभोक्ताओं को हर्जाना (क्षतिपूर्ति) देने का प्रावधान है। लेकिन बिजली कंपनियां इससे बच रही हैं। न तो प्रभावित उपभोक्ताओं को ऐसे प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है और न ही हर्जाना।

हालात यह है कि हर्जाना लेने के लिए आगे आने वालों का यह आंकड़ दहाई से भी कम है। बिजली कंपनियां भी सिर्फ उन्ही मामलों में सक्रिय हैं, जिनमें कोई विद्युत दुर्घटना से मौत हो गई हो या शारीरिक रूप से अक्षम हो गया हो, क्योंकि ऐसे मामलों को छिपाया नहीं जा सकता।

प्रदेश में बनेगी पहली हस्तशिल्प नीति

प्रदेश में हस्तशिल्पी एवं बुनकरों के उत्थान के लिए पहली हस्तशिल्प नीति बनेगी। देश

दुनिया में राजस्थान की पहचान को कायम करने वाले हस्तशिल्प और इन्हें बनाने वाले करीब छह लाख पंजीकृत शिल्पकारों के आर्थिक और सामाजिक प्रोत्साहन के लिए सरकार ने यह कदम बढ़ाया है।

हस्तशिल्प नीति में हस्तशिल्पियों एवं बुनकरों के उत्थान, उनके उत्पादों के लिए बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था के साथ-साथ राज्य के उत्पादों को निर्यात योग्य बनाना व उनकी अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना, रोजगार के नए अवसर सृजित करना एवं अन्य प्रकार से आर्थिक मदद देने जैसे प्रावधान किए जाएंगे।

अपात्र लोगों ने उठाई किसान सम्मान निधि

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में केंद्र सरकार की ओर से गरीब किसानों को सालाना 6000 रुपए का लाभ दिया जाता है। इस योजना से प्रदेश में पहली से छठी किस्त तक 44 लाख 40 हजार 462 अपात्र लोगों ने 62 अरब 16 करोड़ 64 लाख 68 हजार रुपए गरीब किसानों के हड़प लिए। इतना ही नहीं प्रदेश के 70 हजार आयकरदाताओं ने भी किसानों के हक के 100 करोड़ रुपए हड़प लिए।

मामले का खुलासा तब हुआ जब केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की टीमों ने किसानों के आधार कार्ड नंबर व पैन नंबर से उनके दिए गए बैंक खातों का वेरीफिकेशन किया। इसमें खाताधारक व खेत के मालिकों के नाम में अंतर पाया गया। गरीब किसानों की राशि हड़पने वालों में कई करोड़ोंपति हैं। उनके बड़े-बड़े फार्म हाउस हैं। अब ऐसे लोगों के बैंक खातों को फ्रीज कर वसूली होगी।

खुल गया ऑर्गेनिक फ्रेश फार्मर मार्केट

राजस्थान का पहला ऑर्गेनिक उत्पादयुक्त फ्रेश फार्मर मार्केट खुल गया है। भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ के सौजन्य में टोंक रोड, एलआईसी भवन के सामने, प्रताप नगर स्थित इस मार्केट में किसान सीधे अपने खेत के ऑर्गेनिक फल व सब्जियां बेच सकते हैं।

इसके अलावा यहां देशभर की प्रमुख 90 जैविक उत्पाद कंपनियों के उत्पाद भी 5 से 40 फीसदी डिस्काउंट पर ग्राहकों को उपलब्ध होंगे। यहां पांच हजार महिला स्वयं सहायता समूहों को भी हैंड मेड प्रोडेक्ट बेचने के लिए स्थान उपलब्ध कराया गया है। यहां पर उत्पाद बेचने के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा।

ग्रामीण घरों तक पहुंचेगा नल से पानी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जाए।

मिशन के तहत प्रदेशभर में 43 हजार 364 गांवों के करीब एक करोड़ एक लाख घरों को पेयजल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के कामों में गुणवत्ता पर खास ध्यान दिया जाए, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ग्राम स्तर पर समितियों के गठन व टेंडर प्रक्रिया के कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण हों। मिशन के तहत स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है।

बढ़ सकता है बाल विवाह का खतरा

दुनिया में बाल विवाह के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दशक के अंत से पहले 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के एक करोड़ अतिरिक्त बाल विवाह हो सकते हैं। बालिका वधुओं में आधी से ज्यादा संख्या पांच देशों में हैं। इन देशों में भारत भी शामिल है।

संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े संगठन यूनिसेफ की रिपोर्ट 'कोविड-19 ए थ्रेट टू प्रॉग्रेस अंगेस्ट चाइल्ड मैरिज' में यह निष्कर्ष दर्ज है। रिपोर्ट में बताया है कि बच्चों की जल्दी शादी करने एवं युवावस्था में होने वाली मौत के बीच भी सीधा संबंध है। बाल वधुओं के बच्चों में शिशु मृत्यु दर बढ़ने का खतरा अधिक रहता है। यह रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जारी की गई है।

मिट्टी की सेहत हो रही खराब

रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के सहारे ज्यादा पैदावार लेने का लालच धरती की कोख को बांझ बना रहा है। हजारों साल से अजर-अमर मिट्टी की 'सेहत' कुछ ही सालों में इस कदर खराब हो चुकी है कि वह खेती के लायक ही नहीं रही।

इससे न धरती में रोगों से लड़ने की क्षमता बची है और न ही इससे पैदा होने वाले अन्न खाने वालों में। और तो और खेती में बढ़ते रासायनिक उपयोग से धरती के भीतर सुरक्षित माना जाने वाला पानी भी 'जहरीला' हो गया है। इससे लोगों में कैंसर जैसी कई जानलेवा बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है, किसान जैविक खेती अपना कर धरती मां को इस संकट से बचा सकते हैं।

मनरेगा ने रचा रोजगार में नया कीर्तिमान

बीते वर्ष पूरी दुनिया में कोरोना लोगों की आजीविका निगल रहा था। लेकिन इस दौरान राजस्थान में मनरेगा ने प्रभावित लोगों को रोजगार देने के मामले में नए कीर्तिमान बनाए हैं। महामारी के साथ 2020-21 के पूरे वित्तीय वर्ष में राज्य में करीब एक करोड़ 10 लाख लोगों को मनरेगा में रोजगार दिया गया। यह पिछले कई वर्षों की तुलना में सर्वाधिक है।

माना जा रहा है कि इन रोजगारों का सर्वाधिक फायदा उन प्रवासी श्रमिकों को मिला जो दूसरे देश प्रदेश में रोजगार छिनने के बाद राजस्थान लौटे थे। यह भी सामने आया कि जिन जिलों में प्रवासी सर्वाधिक आए, वहां मनरेगा मजदूरों की संख्या बढ़ी। इससे जाहिर है मनरेगा ने राजस्थान लौटे प्रवासियों को सर्वाधिक सहारा दिया।

भूजल का हाल, पाताल में भी पानी नहीं

राजस्थान में भूजल के अत्यधिक दोहन के चलते चार जिलों को छोड़ शेष 29 जिलों के पाताल में भी पानी नहीं बचा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के इन ग्रास सॉफ्टवेयर से 2020 में भूजल के आकलन में यह स्थिति सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और डूंगरपुर जिले ही ऐसे हैं, जहां भूजल की स्थिति ठीक कही जा सकती है।

अधिकारियों का कहना है कि जल संरक्षण के उपाय होने से यह जिले सुरक्षित रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा पिछले दिनों 5 श्रेणियों में ट्यूबवैल खोदने की अनुमति जारी की गई। इसके बाद कितने ट्यूबवैल खोदे गए इसकी जानकारी जिला प्रशासन के पास नहीं है। इससे भूजल की स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक हो गई है।

गहरा रहा है संकट, टीका है इलाज

फिर से कोरोना का संकट बड़ी तेजी से गहराता जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना ही बचाव है। घबराएं नहीं टीका अवश्य लगवाएं।

कोरोना से जंग जीतने के लिए
सरकार के साथ आप भी

जिम्मेदार बनें
पहनिए मास्क

समझदार बनें
धोइए हाथ

लापरवाही नहीं
रखिए दो गज दूरी

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर